

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2062
उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

अल्पसंख्यकों के लिये योजनाएं

2062. श्रीमती संध्या राय:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अल्पसंख्यक समूहों के वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में की गई पहल या अभिकल्पित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और इन योजनाओं पर किए गए खर्च का वर्ष और जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन प्रयासों में प्रभावशीलता का क्या स्तर रहा है; और
- (घ) कर्नाटक और मध्य प्रदेश में प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की जिले-वार संख्या कितनी रही?

उत्तर

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

- (क) मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समूहों के वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली ऐसी कोई योजना/कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
- (ख) से (घ) मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और इन योजनाओं पर होने वाले खर्च का वर्ष और जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

1. शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं

- i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
- ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जिनमें धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। उक्त योजनाओं से अब तक लाभान्वित छात्रों की संख्या का मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार विवरण, मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात <https://www.minorityaffairs.gov.in> पर उपलब्ध है। योजना में लाभार्थियों का जिलेवार विवरण नहीं रखा गया है।

2. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

i) 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' में मंत्रालय की योजनाओं जैसे सीखो और कमाओ (SAK), नई मंजिल, उस्ताद और नई रोशनी को शामिल किया गया है। योजना में लाभार्थियों का जिलेवार विवरण नहीं रखा गया है।

कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य के लिए उपरोक्त योजनाओं के तहत शुरुआत से प्रशिक्षित लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या		
योजना	मध्य प्रदेश	कर्नाटक
सीखो और कमाओ	45,980	9478
नई मंजिल	3644	2368
उस्ताद	2006	45
नई रोशनी	43,975	9875
नया सवेरा	4835	11,018
कुल	1,00,440	32,784

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) अल्पसंख्यकों को पुनर्वित्त मोड पर रियायती ऋण प्रदान करता है जो उन्हें उनके आर्थिक सशक्तीकरण और आजीविका सृजन में सहायता करता है। सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एनएमडीएफसी का सहयोग करती है। एनएमडीएफसी वित्तीय योजनाओं का कार्यान्वयन देश भर में वित्त वर्ष 2021-22 से केनरा बैंक के माध्यम से शुरू हुआ।

इसलिए, एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य में केनरा बैंक द्वारा वितरित रियायती ऋण का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		राशि लाख रु. में	लाभार्थियों की संख्या	राशि लाख रु. में	लाभार्थियों की संख्या
1	भोपाल	9.00	5	0.50	1
2	छिंदवाड़ा	2.00	1		
3	नर्मदापुरम	8.00	2		
	कुल	19.00	8	0.50	1

कर्नाटक

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		राशि लाख रु. में	लाभार्थियों की संख्या	राशि लाख रु. में	लाभार्थियों की संख्या
1	बागलकोट	2.00	3	5.00	5
2	बल्लारी (बेल्लारी)			4.00	4
3	बेलगावी (बेलगाम)	19.00	16	7.00	10
4	बेंगलुरु (बेंगलोर) ग्रामीण			6.00	7
5	बीदर	10	11	12	18
6	चिकबल्लपुर			4	4
7	चिक्कमगलुरु (चिकमगलूर)			2	2
8	दक्षिण कन्नड़			53	88
9	दावणगेरे			2	3
10	धारवाड़			2	4
11	गदग			1	1
12	हसन			3	4
13	कालाबुरागी (गुलबर्गा)	6	2	1	1
14	कोडागू			2	3
15	कोलार			5	8
16	कोप्पल			3	4
17	मंड्या			1	2
18	मैसूर (मैसूर)			4	7
19	रायचुर			3	3
20	रामानगर			4	5
21	शिवमोगगा (शिमोगा)			3.8	4
22	तुमकुरु (तुमकुर)			4.8	5
23	उडुपी			4	4
24	उत्तर कन्नड़ (कारवार)			27	54
25	विजयपुरा (बीजापुर)			18	20
26	यादगीर			3	2
	कुल	37.00	32	184.60	272

3. अवसंरचना विकास योजनाएं

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करेगा।

पीएमजेवीके के तहत शुरुआत से मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है। योजना में लाभार्थियों का जिलेवार विवरण नहीं रखा गया है।

(रु. लाख में)

राज्य	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत इकाइयां	कुल स्वीकृत लागत	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सेदारी
मध्य प्रदेश	स्वास्थ्य परियोजनाएं (जैसे अस्पताल, रेन बसेरा)	2	31766.00	19059.60
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	4	1079.20	647.52
	इंदिरा आवास योजना (IAY)	1000	450.00	337.50
कुल		1006	33295.20	20044.62

(रु. लाख में)

राज्य	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत इकाइयां	कुल स्वीकृत लागत	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा
कर्नाटक	स्वास्थ्य परियोजनाएं (जैसे अस्पताल, लेबर रूम, सीएचसी, पीएचसी आदि)	44	582.00	494.70
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	24	2871.96	1735.25
	इंदिरा आवास योजना (IAY)	5900	2215.00	1661.25
कुल		5968	5668.96	3891.20

सभी योजनाओं ने सम्मिलित रूप से उच्च स्तरीय कौशल हासिल करने, आजीविका में अधिक अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।
